

Daily करेंट अफेयर्स

» 02 जुलाई 2025

NATIONAL AFFAIRS

1. PM मोदी ने नई दिल्ली में आचार्य विद्यानंद जी महाराज के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया।



जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पूज्य जैन संत आचार्य 108 विद्यानंद जी महाराज के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय (MoC) द्वारा नई दिल्ली स्थित भगवान महावीर अहिंसा भारती ट्रस्ट के सहयोग से आयोजित किया गया था।

- यह समारोह आचार्य विद्यानंद जी महाराज को “आचार्य” की उपाधि दिए जाने की 38वीं वर्षगांठ के अवसर पर भी मनाया गया। इस कार्यक्रम ने उनके त्याग, विद्वत्ता, आध्यात्मिक मार्गदर्शन और राष्ट्रीय सेवा से भरे जीवन को सम्मानित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया, तथा भारतीय दार्शनिक परंपराओं और अहिंसा को बढ़ावा देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।

- शताब्दी समारोह 28 जून, 2025 से 22 अप्रैल, 2026 तक चलेगा और इसमें पूरे भारत में सांस्कृतिक कार्यक्रम, शैक्षिक पहल, आध्यात्मिक प्रवचन और साहित्यिक प्रदर्शनियों सहित विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य आचार्य विद्यानंद जी के योगदान के बारे में जागरूकता फैलाना और शांति और अनुशासन के मूल्यों को प्रोत्साहित करना है।

Key Points:-

(i) इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को जैन समुदाय द्वारा “धर्म चक्रवर्ती” की उपाधि से सम्मानित किया गया। यह सम्मान भारतीय आध्यात्मिक मूल्यों, सांस्कृतिक विरासत के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और धर्म, नैतिकता और सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने में उनके नेतृत्व के सम्मान में दिया गया।

(ii) समारोह के हिस्से के रूप में, प्रधानमंत्री मोदी ने आचार्य विद्यानंद जी की जीवन यात्रा पर आधारित एक जीवनी पुस्तक का विमोचन किया, जिसमें उनके तपस्वी अभ्यास, साहित्यिक कार्य, संस्थागत योगदान और सामाजिक सुधार शामिल हैं। इस पुस्तक का उद्देश्य जैन धर्म पर उनके प्रभाव और अहिंसा, एकता और नैतिक शासन के लिए उनकी वकालत का दस्तावेजीकरण करना है।

(iii) शताब्दी वर्ष को और अधिक यादगार बनाने के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत (पर्यटन मंत्रालय और MoT) ने संत की विरासत को श्रद्धांजलि देते हुए एक स्मारक डाक टिकट और 100 रुपये का सिक्का जारी किया। ये डाक टिकट और मौद्रिक रिलीज़ उनके स्थायी प्रभाव की राष्ट्रीय मान्यता का प्रतीक हैं।

2. भूपेंद्र यादव ने मानव-हाथी संघर्ष और संरक्षण पर केंद्रित 21वीं प्रोजेक्ट एलीफेंट बैठक की अध्यक्षता की।



26 जून, 2025 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देहरादून में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी (IGNFA) में प्रोजेक्ट एलीफेंट की 21वीं संचालन समिति की बैठक की अध्यक्षता की। उच्च स्तरीय बैठक में हाथियों के संरक्षण के प्रयासों का आकलन करने और पूरे भारत में मानव-हाथी संघर्ष को संबोधित करने के लिए अधिकारियों, वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों को बुलाया गया।

- अपने आरंभिक भाषण में मंत्री ने मानव-हाथी संघर्ष को कम करने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया, तथा जीवन और आजीविका पर इसके प्रभाव को रेखांकित किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संरक्षण समुदाय द्वारा संचालित होना चाहिए, तथा संरक्षण पहलों की योजना, निगरानी और कार्यान्वयन में स्थानीय आबादी को शामिल करने का आग्रह किया।

- भूपेंद्र यादव ने भारतीय रेलवे, बिजली मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और खनन डेवलपर्स जैसी एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय की भी मांग की। उन्होंने व्यवस्थित रेलवे खंड सर्वेक्षण और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान के माध्यम से ट्रेन की टक्करों के दौरान हाथियों की मौतों को कम करने के प्रयासों पर प्रकाश डाला।

- समिति ने महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रगति की समीक्षा की: उत्तर-पूर्वी राज्यों में समन्वित हाथी जनसंख्या

अनुमान का चरण-1 पूरा हो गया, जिसमें 16,500 से अधिक गोबर के नमूनों का विश्लेषण किया गया। इसके अतिरिक्त, 22 राज्यों से 1,911 बंदी हाथियों के डीएनए प्रोफाइल दर्ज किए गए, जिससे निगरानी और कल्याण योजना को बढ़ावा मिला।

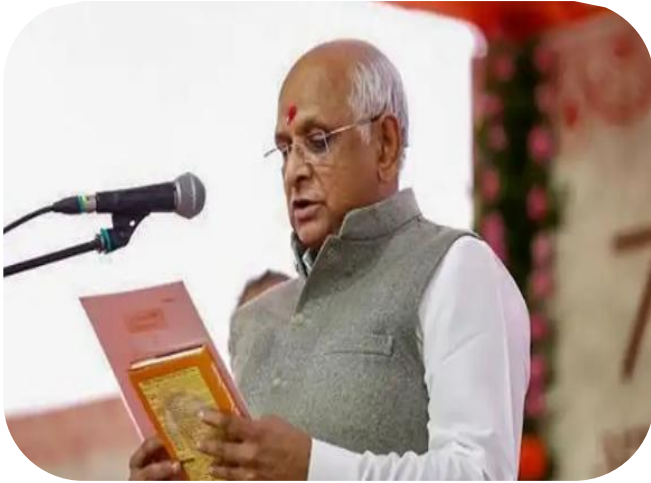
Key Points:-

(i) रेलवे से जुड़ी मौतों पर भी मुख्य ध्यान दिया गया, जिसमें 3,452.4 किलोमीटर संवेदनशील ट्रैक का सर्वेक्षण किया गया और 77 उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान की गई। बैठक में कई ज्ञान संसाधन जारी किए गए- हाथी-ट्रेन टकराव के लिए एक शमन रिपोर्ट, 23 साल का मानव-हाथी संघर्ष अध्ययन (असम, झारखंड, छत्तीसगढ़), सुरक्षित दांत काटने पर एक सलाह, और नवीनतम ट्रम्पेट न्यूज़लेटर।

(ii) भविष्य को देखते हुए, आयोजकों ने कोयंबटूर में विश्व हाथी दिवस (12 अगस्त, 2025) तक एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है, जिसमें गज गौरव पुरस्कार भी शामिल हैं। प्रमुख पहलों में दिसंबर 2025 तक नीलगिरि हाथी संरक्षण योजना को अंतिम रूप देना, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में तीन वर्षीय हाथी-ट्रेकिंग अध्ययन शुरू करना और CAMPA समर्थन के साथ रिजर्व-स्तरीय प्रबंधन प्रदर्शन का मूल्यांकन करना शामिल है।

(iii) यह बैठक सामुदायिक सहभागिता, वैज्ञानिक अनुसंधान, संस्थागत समन्वय और प्रोजेक्ट एलीफेंट के तहत नीति कार्यान्वयन के संयोजन वाली एक एकीकृत रणनीति के माध्यम से हाथियों के संरक्षण के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, जिसे 1992 में परिदृश्य-स्तरीय फोकस के साथ आवासों, गलियारों को संरक्षित करने और संघर्ष को कम करने के लिए शुरू किया गया था।

3. गुजरात ने सामाजिक सुरक्षा पहुंच का विस्तार करने के लिए जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान शुरू किया।



कनुभाई देसाई और प्रमुख सचिव टी. नटराजन सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

Key Points:-

(i) गुजरात वित्तीय समावेशन के मामले में सबसे आगे है, जहाँ लगभग 1.93 करोड़ जन धन खाते हैं, 90 लाख PMJJBY बीमित व्यक्ति हैं, और 1.92 करोड़ PMSBY ग्राहक हैं। अब तक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से ₹21,409 करोड़ हस्तांतरित किए जा चुके हैं, जो राज्य के प्रभावी कल्याणकारी शासन को दर्शाता है।

(ii) कार्यक्रम में विकेंद्रीकृत कार्यान्वयन मॉडल का उपयोग किया जाता है: जिला कलेक्टर, शहरी स्थानीय निकाय, बैंक और क्षेत्रीय अधिकारी जिला कार्य योजनाएँ बनाते हैं। दूरदराज के क्षेत्रों को वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा जाएगा, जिससे दूरदराज के समुदायों तक भी अभियान की पहुँच सुनिश्चित होगी। स्थानीय जवाबदेही इस जमीनी स्तर के अभियान का केंद्र है।

(iii) 2047 तक वित्तीय रूप से समावेशी भारत के व्यापक राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप, यह अभियान डिजिटल साक्षरता और साइबर धोखाधड़ी जागरूकता को संबोधित करता है। यह प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण का समर्थन करता है, इस बात पर बल देता है कि प्रत्येक पात्र नागरिक को सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए, समय पर लाभ मिलना चाहिए और सम्मान के साथ रहना चाहिए।

1 जुलाई, 2025 को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर से जन सुरक्षा समृद्धि अभियान की शुरुआत की। 30 सितंबर तक चलने वाले इस तीन महीने के राज्यव्यापी अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से वंचित न रहे, जिससे प्रधानमंत्री मोदी की "सबका साथ, सबका विकास" पहल के अनुरूप वित्तीय समावेशन और कल्याणकारी वितरण को बढ़ावा मिले।

● यह मिशन पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीवाई), पीएम सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), अटल पेंशन योजना (एपीवाई) और प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) जैसी प्रमुख सरकारी योजनाओं के तहत वंचित लाभार्थियों की घर-घर जाकर पहचान करने और मौके पर ही नामांकन करने पर केंद्रित है। यह योजना कवरेज में सुधार के लिए केवाईसी विवरण अपडेट करने और जन धन खाते खोलने पर भी जोर देता है।

● अभियान के शुभारंभ पर, सीएम पटेल ने तीन लाभार्थियों को पीएमएसबीवाई के तहत ₹2 लाख के चेक वितरित करके और जन धन पासबुक जारी करके समर्थन का प्रतीक पेश किया, जो इस पहल के माध्यम से ठोस वित्तीय सशक्तिकरण को दर्शाता है। इस कार्यक्रम की देखरेख के लिए वित्त मंत्री

4. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में भारत के पहले ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला रखी।



26 जून, 2025 को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के साथ मिलकर देश के पहले ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला रखी। यह 1,000 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला 30 मेगावाट का अत्याधुनिक सुविधा केंद्र है, जिसे सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (CEL) ने ESDS के साथ साझेदारी में बनाया है। यह गाजियाबाद के साहिबाबाद में स्थित है।

- DSIR (वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग) के तहत एक मिनी-रत्न पीएसयू CEL द्वारा विकसित यह परियोजना अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा-कुशल वास्तुकला पर एक मजबूत फोकस को दर्शाती है। टियर-III प्रमाणन, उन्नत शीतलन प्रणाली, परावर्तक छत, वर्षा जल संचयन और 40 Gbps फाइबर बैकबोन से लैस, यह टिकाऊ ICT बुनियादी ढांचे के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

- उत्तर प्रदेश का लक्ष्य 2027 तक 20,000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पन्न करना है, जिसमें यह डेटा सेंटर उत्प्रेरक की भूमिका निभाएगा। ₹1,000 करोड़ का निवेश 2022 के बाद से यूपी का छठा प्रमुख डेटा सेंटर है और राज्य के बढ़ते डिजिटल इकोसिस्टम में बढ़ती निजी-सार्वजनिक भागीदारी का संकेत देता है।

- CM योगी आदित्यनाथ ने राज्य के परिवर्तन पर प्रकाश डाला, जिसमें 2017 से GDP और प्रति व्यक्ति

आय में 2.5 गुना वृद्धि और गरीबी में उल्लेखनीय कमी का हवाला दिया गया, जिससे 6 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल आए। उन्होंने CEL के विनिवेश से लेकर मुनाफे तक के पुनरुद्धार की प्रशंसा की, और "विकसित भारत @2047" के विजन को पूरा करने में इसकी भूमिका को रेखांकित किया।

Key Points:-

(i) ग्रीन डेटा सेंटर CEL और ESDS के बीच एक सहयोग है, जिसमें प्रति मंजिल 200 उच्च घनत्व वाले रैक, टियर-III अपटाइम और पर्यावरण के अनुकूल संचालन सुनिश्चित करने के लिए ग्रीन बिल्डिंग मानक शामिल हैं। इससे क्षेत्र में डिजिटल विकास, नवाचार और कुशल रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

(ii) केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 1977 में भारत का पहला सौर सेल स्थापित करने में सीईएल के ऐतिहासिक नवाचार का उल्लेख किया, तथा संगठन के मामूली शुरुआत से लेकर अग्रणी टिकाऊ डिजिटल बुनियादी ढांचे तक के परिवर्तन की सराहना की। यह परियोजना नोएडा में क्वांटम यूनिट और लखनऊ में नियोजित बायोटेक पार्क जैसी पहलों के साथ संरेखित है।

(iii) उन्नत हरित प्रौद्योगिकियों और उच्च अपटाइम मानकों को एकीकृत करके, यह केंद्र यूपी को डिजिटल इंडिया और ग्रीन इंडिया जैसी राष्ट्रीय डिजिटल परिवर्तन रणनीतियों में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करता है, साथ ही 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन के लिए भारत की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं का भी समर्थन करता है।

5. CEA ने नई दिल्ली में विद्युत सुरक्षा दिवस 2025 पर राष्ट्रव्यापी विद्युत सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया।



26 जून, 2025 को, विद्युत मंत्रालय (MoP) के तहत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) ने बॉम्बे उपनगरीय विद्युत आपूर्ति (BSES) के साथ साझेदारी में, विद्युत सुरक्षा दिवस 2025 को चिह्नित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी विद्युत सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया गया और भारत के ऊर्जा क्षेत्र में सुरक्षित विद्युत प्रथाओं को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

- यह कार्यक्रम एक राष्ट्रीय पहल के रूप में कार्य करता है, जिसका उद्देश्य एक क्षति रहित, टिकाऊ विद्युत पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करना है, विशेष रूप से स्मार्ट ऊर्जा परिवर्तन और विद्युत अवसंरचना में सुरक्षा-प्रथम प्रथाओं के लक्ष्यों के साथ संरेखण में।

- विद्युत सुरक्षा दिवस 2025 का विषय 'स्मार्ट ऊर्जा, सुरक्षित राष्ट्र' था, जो देश भर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS), इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बुनियादी ढांचे और छत पर सौर ऊर्जा प्रतिष्ठानों जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में सुरक्षा तंत्र को एकीकृत करने की बढ़ती आवश्यकता पर बल देता है।

- इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री (MoS) श्रीपद येसो नाइक ने किया, जो विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) दोनों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उनके साथ पंकज अग्रवाल (सचिव, विद्युत मंत्रालय),

घनश्याम प्रसाद (अध्यक्ष, CEA) और अमल सिन्हा (निदेशक एवं CEO, BSES) सहित वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए, जिन्होंने सामूहिक रूप से विद्युत सुरक्षा के महत्व पर बात की।

Key Points:-

(i) इस कार्यक्रम में उपयोगिताओं, विनियामक प्राधिकरणों, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWAs) और राज्य मुख्य विद्युत निरीक्षण कार्यालयों के 300 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विशेष आकर्षणों में सुरक्षा शुभंकर 'सुरक्षा शक्ति' का शुभारंभ और विद्युत सुरक्षा पुस्तिका का पहला संस्करण शामिल था, जिसे घरों, ईवी चार्जिंग स्टेशनों और छतों पर सौर ऊर्जा प्रणालियों के लिए सुरक्षित बिजली प्रथाओं का मार्गदर्शन करने के लिए CEA और BSES द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था।

(ii) विद्युत सुरक्षा पुस्तिका में विद्युत उपयोगिताओं, उपभोक्ताओं, प्रोसुमर्स और फील्ड तकनीशियनों के लिए आवश्यक क्या करें और क्या न करें की जानकारी दी गई है। यह बिजली के खतरों जैसे कि झटके, आग और बुनियादी ढांचे की खराबी से निपटने के लिए एक संदर्भ पुस्तिका के रूप में कार्य करता है, जिसमें अगली पीढ़ी की ऊर्जा प्रणालियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

(iii) इस कार्यक्रम में CEA, BSES, NPTI (राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान) और ऊर्जा क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञों द्वारा ग्राउंडिंग और अर्थिंग प्रणालियों पर तकनीकी प्रस्तुतियां, प्रदर्शन और पैनल इंटरैक्शन भी शामिल थे।

INTERNATIONAL

1. वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत 115वें स्थान पर पहुंचा और आइसलैंड शीर्ष स्थान पर बरकरार।

GLOBAL PEACE INDEX 2025



Iceland retains top spot

जून 2025 में सिडनी स्थित थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस (IEP) ने ग्लोबल पीस इंडेक्स (GPI) का 19वां संस्करण जारी किया। भारत 2.229 स्कोर के साथ 116वें स्थान से 115वें स्थान पर पहुंच गया, जबकि आइसलैंड 1.095 स्कोर के साथ शीर्ष वैश्विक रैंक पर बना रहा।

- GPI 2025 ने 163 देशों का मूल्यांकन किया, जिसमें दुनिया की 99.7% आबादी शामिल थी। इसमें तीन क्षेत्रों में 23 संकेतकों का इस्तेमाल किया गया: सामाजिक सुरक्षा और संरक्षा, जारी घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष और सैन्यीकरण। स्कोर 1 (सबसे शांतिपूर्ण) से लेकर 5 (सबसे कम शांतिपूर्ण) तक होता है।

- आइसलैंड एक बार फिर 1.095 स्कोर के साथ सबसे शांतिपूर्ण देश बना, लगातार 17वें साल शीर्ष स्थान पर रहा। यह अन्य उच्च रैंकिंग वाले देशों आयरलैंड, न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड से आगे रहा।

Key Points:-

(i) 115वें स्थान पर, भारत ने अपने GPI स्कोर में थोड़ा सुधार किया और पिछले साल के 116वें स्थान से 2.229 पर पहुंच गया। यह 2023 में 126वें और 2019 में 141वें स्थान से क्रमिक प्रगति को दर्शाता है, जो बेहतर सुरक्षा, संरक्षा और कम संघर्ष को दर्शाता है। दक्षिण एशिया में, भारत ने बांग्लादेश (123),

पाकिस्तान (144) और अफ़गानिस्तान (158) से बेहतर प्रदर्शन किया।

(ii) 2025 के सूचकांक में वैश्विक शांति में 0.36% की गिरावट दिखाई गई है - 17 वर्षों में 13वीं गिरावट। जबकि 74 देशों में सुधार हुआ, 87 देशों में शांति का स्तर बिगड़ता हुआ देखा गया, जो चल रही भू-राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ते वैश्विक तनाव को उजागर करता है।

(iii) सूची में सबसे नीचे रूस 163वें (सबसे कम शांतिपूर्ण) स्थान पर है, यूक्रेन 162वें स्थान पर है, तथा उसके बाद सूडान, DR कांगो और यमन सबसे कम शांतिपूर्ण देशों में शामिल हैं।

2. पाकिस्तान ने शांति और बहुपक्षवाद पर ध्यान केंद्रित करते हुए जुलाई 2025 तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली।



1 जुलाई, 2025 को पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर जुलाई महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली, जो कि एक अस्थायी सदस्य के रूप में दो साल का कार्यकाल होगा। राजदूत असीम इफ़्तिखार अहमद ने शांति, संघर्ष समाधान और संयुक्त राष्ट्र चार्टर को बनाए रखने पर केंद्रित पारदर्शी, समावेशी नेतृत्व का वचन देते हुए कमान संभाली।

- संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक प्रेस ब्रीफ़िंग के दौरान, राजदूत अहमद ने “शांतिपूर्ण विवाद

समाधान और अंतराष्ट्रीय कानून” के प्रति पाकिस्तान की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। इजरायल-फिलिस्तीन स्थिति और क्षेत्रीय कूटनीति जैसे मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने आश्वासन दिया कि पाकिस्तान के नेतृत्व में परिषद वैश्विक संकटों के प्रति उत्तरदायी रहेगी।

● पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने बहुपक्षीय सहयोग और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रति देश की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने दो उच्च स्तरीय सत्रों की घोषणा की: एक अंतरराष्ट्रीय शांति और विवाद समाधान को बढ़ावा देने पर, और दूसरा इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के साथ संयुक्त राष्ट्र सहयोग पर।

Key Points:-

(i) पाकिस्तान की अध्यक्षता सुरक्षा परिषद में उसके आठवें कार्यकाल के बाद हुई है, जिसे जून 2024 में 182 मतों के साथ चुना गया था। घूर्णनशील अध्यक्षता, हालांकि काफी हद तक प्रतीकात्मक है, इस्लामाबाद को एजेंडा और स्वर को निर्देशित करने का अधिकार देती है, जिससे उसे वैश्विक शांति और सुरक्षा पर विचार-विमर्श को प्रभावित करने का एक मंच मिलता है।

(ii) मासिक अध्यक्षता पाकिस्तान को वैश्विक मामलों पर परिषद की बैठकें आयोजित करने की अनुमति देती है। जुलाई 2025 के लिए, फोकस क्षेत्रों में इजरायल-फिलिस्तीन मुद्दे को मंत्री स्तर तक उठाना, मानवीय संकटों को संबोधित करना और विशेष रूप से ओआईसी के साथ संयुक्त राष्ट्र-क्षेत्रीय संगठन सहयोग को मजबूत करना शामिल है।

(iii) यह घटनाक्रम वैश्विक उथल-पुथल के बीच हुआ है - मध्य पूर्व, यूक्रेन, अफ्रीका और दक्षिण एशिया में तनाव बढ़ रहा है। पाकिस्तान की बारी-बारी से अध्यक्षता उसे कूटनीतिक जुड़ाव, संवाद और बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने की स्थिति में रखती है, ऐसे समय में जब वैश्विक संस्थाएँ विश्वास और

प्रभावशीलता की चुनौतियों का सामना कर रही हैं।

3. वैश्विक उपग्रह तैनाती 2025: अमेरिका 8,530 उपग्रहों के साथ अग्रणी और भारत 136 के साथ 7वें स्थान पर।



2025 के लिए हाल ही में जारी की गई उद्योग रिपोर्ट में दुनिया भर में उपग्रहों की तैनाती में वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका 8,530 उपग्रहों के साथ इस सूची में सबसे आगे है, जबकि भारत 136 उपग्रहों के प्रक्षेपण के साथ 7वें स्थान पर है। यह भारी वृद्धि तेजी से बढ़ते वाणिज्यिक विस्तार, छोटे उपग्रहों के समूह और वैश्विक अंतरिक्ष अवसंरचना में बढ़ती राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को रेखांकित करती है।

● 2025 की शुरुआत में उपग्रह नेटवर्क के विस्तार में रिकॉर्ड उछाल आया, जनवरी और अप्रैल के बीच 1,200 से अधिक उपग्रह प्रक्षेपित किए गए - 2024 की इसी अवधि की तुलना में 50% की वृद्धि। यह उछाल काफी हद तक SpaceX और अमेज़ॉन के प्रोजेक्ट कुइपर जैसी कंपनियों के वाणिज्यिक मेगा-तारामंडल द्वारा संचालित है।

● 8,530 सक्रिय उपग्रहों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका अंतरिक्ष में अग्रणी बना हुआ है। इसके उपग्रहों में निम्न-पृथ्वी अवलोकन और ब्रॉडबैंड सिस्टम से लेकर रक्षा और नेविगेशन प्लेटफॉर्म तक शामिल हैं। यह वैश्विक स्तर पर सभी वाणिज्यिक

प्रक्षेपण गतिविधियों में से लगभग आधे के लिए जिम्मेदार है।

● 136 सक्रिय उपग्रहों के साथ भारत ने दुनिया भर में अपना 7वां स्थान सुरक्षित कर लिया है। अमेरिका या चीन से छोटा होने के बावजूद, भारत की वृद्धि ISRO, NSIL और उभरते निजी खिलाड़ियों के मिश्रण से आती है जो संचार, पृथ्वी अवलोकन और नाविक जैसी नेविगेशन प्रणालियों में योगदान दे रहे हैं।

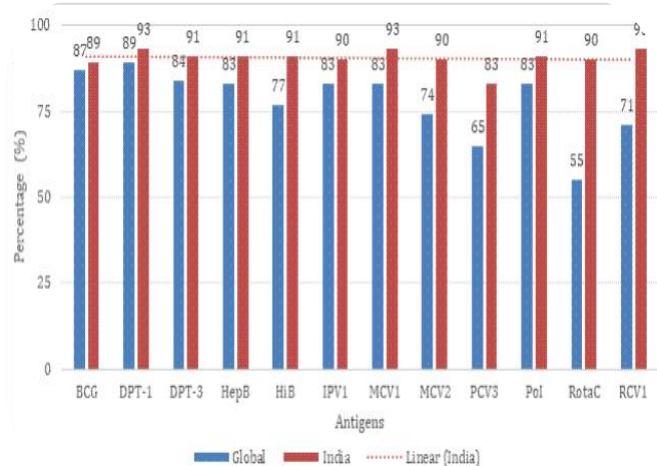
Key Points:-

(i) भारत के उपग्रह पारिस्थितिकी तंत्र में ISRO के नेतृत्व में प्रक्षेपण, निजी समूह और SBS-III जैसे कार्यक्रमों के तहत रक्षा तैनाती शामिल है, जिसके तहत 2029 तक 52 सैन्य निगरानी उपग्रहों की योजना है। यह वृद्धि राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतरिक्ष क्षमता को बढ़ाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।

(ii) SpaceX वाणिज्यिक प्रक्षेपणों में अपना दबदबा बनाए हुए है, अकेले 2025 की शुरुआत में 573 स्टारलैंक उपग्रहों को तैनात किया जाएगा। इस बीच, अमेज़ॉन के प्रोजेक्ट कुइपर ने शुरुआती सफलताओं के साथ शुरुआत की, जिसने वैश्विक इंटरनेट-फ्रॉम-स्पेस सेवाओं में प्रतिस्पर्धा का संकेत दिया।

(iii) इस तीव्र स्केलिंग से अंतरिक्ष मलबे और कक्षीय भीड़भाड़ की चिंताएँ पैदा होती हैं। विशेषज्ञ सख्त अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन, डीऑर्बिट प्रोटोकॉल और टिकाऊ संचालन का आग्रह करते हैं। उपग्रह बाजार में वैश्विक निवेश 2025 में 480 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है, जो व्यावसायीकरण के रुझान और विनियमन की आवश्यकता को उजागर करता है।

4. संयुक्त राष्ट्र IGME रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 2024 तक सभी नियमित टीके न लगवाने वाले बच्चों की संख्या 0.11 प्रतिशत से घटकर 0.06 प्रतिशत रह जाएगी।



हाल ही में संयुक्त राष्ट्र IGME 2024 की रिपोर्ट और स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, भारत में शून्य खुराक वाले बच्चों (जिन्हें एक भी नियमित टीका नहीं मिला है) का प्रतिशत 2023 में 0.11% से 2024 में 0.06% तक महत्वपूर्ण रूप से कम हो गया है - तीव्र टीकाकरण अभियान और लक्षित पहुंच से इसमें मदद मिली है।

● भारत का सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP) अब 12 टीका-निवारणीय रोगों को कवर करता है, जो 1.3 करोड़ से अधिक टीकाकरण सत्रों के माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग 2.6 करोड़ शिशुओं और 2.9 करोड़ गर्भवती महिलाओं को सेवाएं प्रदान करता है - जो टीकाकरण अंतराल को कम करने के लिए एक आवश्यक बुनियादी ढांचा है।

● एक प्रमुख पहल रही है ज़ीरो डोज़ कार्यान्वयन योजना 2024, जिसे 11 राज्यों के 143 जिलों में शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य शहरी झुगियों, प्रवासी समुदायों और दुर्गम इलाकों में रहने वाले अटीकृत (unvaccinated) बच्चों तक पहुँचना है। इसे सशक्त सामुदायिक भागीदारी और U-WIN जैसे डिजिटल ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से और मज़बूत बनाया गया है।

● सरकार ने भारत की सफलता का श्रेय मिशन इंद्रधनुष को दिया, जो 2014 से चल रहा है, जिसके तहत 5.46 करोड़ से अधिक बच्चों और 1.32 करोड़ गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया है -

जिससे पोलियो (2014) और नवजात टेटनस (2015) को खत्म करने के प्रयासों को बल मिला है, तथा 2025 में एक नया खसरा-रूबेला अभियान शुरू किया गया है।

Key Points:-

(i) भारत की प्रगति को मार्च 2024 में अमेरिकन रेड क्रॉस मुख्यालय में प्रदान किए गए मीजल्स और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से वैश्विक मान्यता मिली और भारत को बाल स्वास्थ्य में एक "वैश्विक उदाहरण" के रूप में स्थापित किया।

(ii) टीकाकरण के साथ-साथ, बाल मृत्यु दर में उत्साहजनक रुझान - पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में 78% की गिरावट और नवजात शिशुओं में उल्लेखनीय सुधार - टीकाकरण और उन्नत मातृ-शिशु स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के व्यापक प्रभाव को रेखांकित करते हैं।

(iii) सरकारी सूत्रों ने इस बात पर जोर दिया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शून्य खुराक वाले बच्चों की वास्तविक संख्या की तुलना करने पर भारत के विशाल जनसंख्या आधार और उच्च कवरेज को नजरअंदाज कर दिया जाता है, जिससे भारत का 0.06% आंकड़ा दुनिया में सर्वश्रेष्ठ में से एक बन जाता है।

5. 2025 बॉन जलवायु सम्मेलन विभाजित परिणामों और वित्तीय रोडमैप वार्ता के साथ संपन्न हुआ।



62वां Bonn जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 16 से 26 जून, 2025 तक जर्मनी के Bonn में UNFCCC के सहायक निकायों के तहत आयोजित किया गया था। जबकि अनुकूलन वित्त और न्यायोचित संक्रमण दिशा-निर्देशों पर प्रगति हुई, वार्ता ने जलवायु वित्त प्रतिबद्धताओं, एजेंडा असहमति और बेलेम में COP30 के लिए उभरती तैयारियों पर गहरे मतभेदों को उजागर किया।

● पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 पर एजेंडा मर्दों और यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) जैसे एकतरफा व्यापार उपायों पर विवाद के कारण वार्ता लगभग दो दिन की देरी से शुरू हुई। भारत सहित विकासशील देशों ने आगे बढ़ने से पहले औपचारिक समावेश पर जोर दिया।

● जस्ट ट्रांजिशन वर्क प्रोग्राम के तहत, प्रतिनिधियों ने जीवाश्म ईंधन से दूर जाने के लिए "पूरी अर्थव्यवस्था" के दृष्टिकोण पर सहमति व्यक्त की। हालांकि कुछ आम सहमति बनी, लेकिन नौकरी की सुरक्षा और समानता पर विकसित और विकासशील देशों के बीच अंतर्निहित तनाव अनसुलझा रहा।

Key Points:-

(i) अनुकूलन के मामले में, एक बड़ी उपलब्धि वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य (GGA) संकेतकों पर आम सहमति बनना थी, जो हजारों से घटकर 500 के आसपास रह

गई। हालांकि, इन संकेतकों में जलवायु वित्त तंत्र को शामिल करने के बारे में बहस जारी रही।

(ii) विकासशील देशों—जिन्हें G77+चीन, LMDC (Like-Minded Developing Countries), AOSIS (Alliance of Small Island States), LDCs (Least Developed Countries), और AGN (African Group of Negotiators) जैसे समूहों का समर्थन प्राप्त है—ने अनुच्छेद 9.1 के दायित्वों की स्पष्टता और अनुकूलन (adaptation) एवं हानि-नुकसान (loss-and-damage) के लिए पारदर्शी वित्तीय सहायता की माँग की। यह माँग विश्वास की निरंतर कमी को दर्शाती है।

(iii) Bonn ने निष्कर्ष निकाला कि पार्टियों ने प्रगति को स्वीकार किया, लेकिन ब्राजील के बेलेम में होने वाले COP30 से पहले प्रयासों को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। मुख्य चिंताएँ बनी हुई हैं: वित्तीय रोडमैप को अंतिम रूप देना, जलवायु महत्वाकांक्षा को बढ़ाना, और शमन, अनुकूलन और वित्त में न्यायसंगत, विज्ञान-आधारित कार्रवाई सुनिश्चित करना।

MOUs and Agreement

1. MYAS और DIC ने उन्नत "MY भारत 2.0" युवा मंच बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।



30 जून, 2025 को, युवा मामले और खेल मंत्रालय (MYAS) ने MeitY के तहत डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन (DIC) के साथ साझेदारी की, नई दिल्ली में मौजूदा युवा जुड़ाव पोर्टल को MY Bharat2.0 में अपग्रेड करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए - जो कि युवा सशक्तिकरण को मजबूत करने के उद्देश्य से एक डिजिटल रूप से सशक्त, AI-संचालित सिंगल-विंडो प्लेटफॉर्म है।

● **केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया** (युवा मामले एवं खेल, श्रम एवं रोजगार) और **अश्विनी वैष्णव** (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी, रेलवे और सूचना एवं प्रसारण) की मौजूदगी में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें उच्च स्तरीय प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया। DoYA, MeitY और DIC के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया, जिसमें **नितेश कुमार मिश्रा** (DoYA) और **नंद कुमारम** (DIC) ने समझौते को क्रियान्वित किया।

● **MY Bharat2.0** को एंड्रॉइड और iOS के लिए एक बेहतर, पूरी तरह कार्यात्मक मोबाइल ऐप के साथ मॉड्यूलर आर्किटेक्चर पर फिर से बनाया जाएगा। यह आधार, डिजिलॉकर, भाषानी और MyGov जैसे राष्ट्रीय डिजिटल बुनियादी ढांचे को एकीकृत करेगा, जिससे स्केलेबिलिटी, समावेशिता और इंटरऑपरेबिलिटी सुनिश्चित होगी।

● उन्नत पोर्टल में स्मार्ट CV बिल्डर, व्यक्तिगत डिजिटल प्रोफाइल, AI चैटबॉट, जियो-टैगिंग, वॉयस-असिस्टेड नेविगेशन और स्पीच-टू-टेक्स्ट टूल जैसी AI-संचालित सुविधाएँ शामिल होंगी। बैकएंड सपोर्ट में कॉल सेंटर, प्रशिक्षण मॉड्यूल, MIS डैशबोर्ड और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं - जो दूरदराज और शहरी क्षेत्रों के युवाओं की सहायता के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

Key Points:-

(i) MYAS सचिव डॉ. पल्लवी जैन गोविल ने पोर्टल की युवा-केंद्रित पेशकशों पर प्रकाश डाला: राष्ट्रीय

करियर सेवाएं, मेंटरशिप हब और फिट इंडिया सेक्शन, जिसका उद्देश्य करियर, नागरिक जुड़ाव और कल्याण को कवर करते हुए समग्र विकास करना है।

(ii) 1.76 करोड़ से ज़्यादा युवा उपयोगकर्ताओं और 1.19 लाख संगठनों के साथ, MY Bharat2.0 का लक्ष्य "विकसित भारत 2047" विज़न के तहत भारत के जनसांख्यिकीय लाभ को विकास लाभांश में बदलना है। डॉ. मंडाविया ने इसे सिर्फ एक डिजिटल टूल से ज़्यादा बताया- यह "सेवाभाव" और नागरिक उद्देश्य से प्रेरित एक आंदोलन है।

App and Web Portal

1. भारतीय रेलवे ने यात्री सेवाओं को एकीकृत करने के लिए "रेलवन" सुपर ऐप लॉन्च किया।



1 जुलाई, 2025 को भारतीय रेलवे ने CRIS (सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम) के साथ मिलकर RailOne नाम से एक एकीकृत मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जो सभी प्रमुख यात्री सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करता है। इस ऐप का अनावरण रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में CRIS के 40वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान किया।

● रेलवन सुपर ऐप IRCTC (भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम) टिकटिंग, UTS (अनारक्षित

टिकटिंग सिस्टम) और NTES (राष्ट्रीय ट्रेन पूछताछ प्रणाली) सहित नौ आवश्यक सेवाओं को एक सहज प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करता है। यात्री अब एक ही इंटरफ़ेस से आरक्षित और अनारक्षित टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट और सीज़न पास बुक कर सकते हैं।

● इस ऐप में रियल-टाइम PNR (यात्री नाम रिकॉर्ड) स्टेटस अपडेट, कोच पोजिशन लोकेटर और लाइव ट्रेन ट्रैकिंग जैसी उन्नत सुविधाएँ शामिल हैं, जो यात्रियों की सुविधा और यात्रा नियोजन सटीकता को बढ़ाती हैं। ये सुविधाएँ ट्रेन से संबंधित अपडेट को ट्रैक करने के लिए कई ऐप्स के बीच स्विच करने की ज़रूरत को खत्म कर देती हैं।

● IRCTC ई-कैटरिंग के ज़रिए भोजन ऑर्डर करना एकीकृत है, जिससे यात्री स्वीकृत विक्रेताओं से भोजन बुक कर सकते हैं और उन्हें सीधे अपनी सीट पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, स्पष्ट ट्रैकिंग के साथ एक सरलीकृत रिफंड प्रक्रिया उपयोगकर्ता की संतुष्टि और विफल लेनदेन या रद्दीकरण के लिए प्रतिक्रिया समय में सुधार करती है।

Key Points:-

(i) RailOne आर-वॉलेट के माध्यम से बायोमेट्रिक लॉगिन और mPIN (मोबाइल पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर) सुरक्षा भी प्रदान करता है, बहुभाषी पहुंच का समर्थन करता है, और इसमें रेल मदद (संकट के दौरान प्रत्यक्ष सहायता और सहायता के लिए रेलवे मोबाइल एप्लिकेशन) के माध्यम से एक अंतर्निहित शिकायत निवारण मॉड्यूल शामिल है। यह IRCTC और UTS में सिंगल साइन-ऑन (SSO) कार्यक्षमता का भी समर्थन करता है।

(ii) IRCTC रेल कनेक्ट, UTS मोबाइल ऐप, NTES, रेल मदद और ई-कैटरिंग जैसे कई प्लेटफॉर्म को एक ऐप में मिलाकर, रेलवन सार्वजनिक परिवहन में सेवा वितरण और डिजिटल एकीकरण को बेहतर बनाने के

लिए डिजिटल इंडिया पहल के साथ जुड़ता है। यह यात्रियों के लिए डिजिटल अव्यवस्था को काफी हद तक कम करता है।

(iii) लॉन्च के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे को सार्वजनिक सेवा आधुनिकीकरण में एक "क्रांतिकारी कदम" बताया। उन्होंने इसे भारतीय रेलवे को दक्षता, सुविधा और पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध एक विश्व स्तरीय, डिजिटल रूप से सशक्त परिवहन प्रणाली में बदलने की दिशा में CRIS की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया।

IMPORTANT DAYS

1. अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस 30 जून 2025 को मनाया गया।

INTERNATIONAL DAY OF PARLIAMENTARISM



JUNE 30

विश्व स्तर पर 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया जाता है, ताकि लोकतांत्रिक शासन, जवाबदेही और प्रतिनिधित्व में संसदों की भूमिका को पहचाना जा सके। यह 30 जून 1889 को स्थापित अंतर-संसदीय संघ (IPU) की वर्षगांठ का प्रतीक है।

• इस दिन को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2018 में प्रस्ताव A/RES/72/278 के माध्यम से नामित किया गया था ताकि लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने, सार्वजनिक आवाज को सुविधाजनक बनाने और दुनिया भर में विधायी

पारदर्शिता को बढ़ावा देने में संसदों के महत्व को उजागर किया जा सके।

• 2025 में, थीम "लैंगिक समानता प्राप्त करना: कार्रवाई द्वारा कार्रवाई" है, जो बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन की 30वीं वर्षगांठ के साथ संरेखित है। इस बात पर ध्यान केंद्रित किया जाता है कि संसदें लैंगिक अंतर को कम करने और राजनीति में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कानूनी सुधार और संस्थागत तंत्र कैसे चला सकती हैं।

• संसद कानून बनाने, बजट अनुमोदन, नीति निरीक्षण और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे शासन में जांच और संतुलन भी सुनिश्चित करते हैं, नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं और जलवायु और शांति से संबंधित कानून का समर्थन करते हैं।

Key Points:-

(i) लोकतांत्रिक शासन, जवाबदेही और प्रतिनिधित्व में संसदों की भूमिका को मान्यता देने के लिए 30 जून को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया जाता है। यह 30 जून 1889 को स्थापित अंतर-संसदीय संघ (IPU) की वर्षगांठ का प्रतीक है।

(ii) जिनेवा, स्विटजरलैंड में मुख्यालय वाला अंतर-संसदीय संघ (IPU) 179 राष्ट्रीय संसदों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। यह युवा भागीदारी, लैंगिक समानता, डिजिटल अनुकूलन और वैश्विक संसदीय कूटनीति पर प्रगति की निगरानी करता है।

(iii) यह दिवस बढ़ती सत्तावादी प्रवृत्तियों के बीच लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास को सुदृढ़ करने, अधिक सार्वजनिक सहभागिता और संस्थागत सुधारों को प्रोत्साहित करने का कार्य करता है, जो लोकतंत्रों को अधिक समावेशी और जवाबदेह बनाते हैं।

2. राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस 2025 – 1 जुलाई को मनाया गया।



भारत हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस मनाता है, जो 1949 में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) की स्थापना का प्रतीक है। यह दिन भारत के वित्तीय, नियामक और आर्थिक ढांचे को मजबूत करने में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (CA) के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देता है।

- भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (ICAI) की स्थापना 1 जुलाई 1949 को भारत की संसद द्वारा पारित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के तहत की गई थी। यह भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।

- ICAI दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अकाउंटिंग संस्था है, जिसके 2.5 लाख से ज़्यादा सदस्य हैं और भारत में इसकी 165 से ज़्यादा शाखाएँ और 44 विदेशी शाखाएँ हैं। यह CA पेशे को नियंत्रित करता है, पेशेवर मानकों को बनाए रखता है और देश भर में CA परीक्षाएँ आयोजित करता है।

Key Points:-

(i) चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटिंग, वित्तीय रिपोर्टिंग, कर परामर्श, फॉरेंसिक अकाउंटिंग और अनुपालन और जोखिम पर व्यवसायों को सलाह देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सरकारी ऑडिट, नीति कार्यान्वयन और स्टार्टअप इकोसिस्टम विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

(ii) पहले भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट गोपालदास पद्मसे कपाड़िया थे, जो ICAI के पहले अध्यक्ष भी बने। पहली भारतीय महिला सीए आर. शिवभोगम थीं, जिन्होंने 1933 में योग्यता प्राप्त की और 1950 में ICAI के गठन के बाद इसमें शामिल हुईं।

(iii) वर्ष 2025 में 77वां CA दिवस मनाया जाएगा, जिसे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्यक्रमों, सेमिनारों, स्टार्टअप मेंटरशिप ड्राइव और ICAI पुरस्कार समारोहों के साथ मनाया जाएगा ताकि देश के वित्तीय विकास में योगदान देने वाले असाधारण CA को सम्मानित किया जा सके।

Static GK

Ministry of Culture (MoC)	केंद्रीय मंत्री: श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत	मुख्यालय: नई दिल्ली
Gujarat	मुख्यमंत्री: भूपेन्द्र पटेल	राज्यपाल: आचार्य देवव्रत
Uttar Pradesh	मुख्यमंत्री: योगी आदित्यनाथ	राज्यपाल: आनंदीबेन पटेल
MYAS	कैबिनेट मंत्री: मनसुख मंडाविया	मुख्यालय: नई दिल्ली
Iceland	राजधानी: रेक्जाविक	आधिकारिक भाषा: आइसलैंडिक
Central Electricity Authority (CEA)	अध्यक्ष : घनश्याम प्रसाद	मुख्यालय: नई दिल्ली
Centre for Railway Information Systems (CRIS)	अध्यक्ष और MD : GVL सत्य कुमार	मुख्यालय: नई दिल्ली
Pakistan	राजधानी: इस्लामाबाद	राष्ट्रपति: आसिफ अली जरदारी
USA	राजधानी: वाशिंगटन, डी.सी.	राष्ट्रपति: डोनाल्ड ट्रम्प

Germany	राष्ट्रपति: फ्रैंक-वाल्टर स्टीनमीयर	चांसलर: फ्रेडरिक मेर्ज़
---------	-------------------------------------	-------------------------